Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025
fb: https://www.facebook.com/PopularFrontofIndiaOfficial/ website: www.popularfrontindia.org
email: popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902

प्रेस रिलीज़
09 मई 2018
नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय की गरिमा, साख और उसके मूल्यों की रक्षा करो

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में पारित प्रस्ताव में उच्च्तम न्यायालय के मूल्यों के उल्लंघन पर गहरी चिंता व्यक्त की है और देश की जनता से अपील की है कि वे उसकी गरिमा और साख को कमज़ारे करने की कोशिशों के खिलाफ आगे आएं।

हाल के कुछ घटनाक्रमों से देश के सबसे सीनियर जजों के बीच बढ़ते तनाव और उच्चतम न्यायालय में राजनैतिक हस्तक्षेप के आरोप की बात सामने आई है। याद रहे कि जजों के एक समूह के पास जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो उन्हें मजबूरन जनता के बीच आना पड़ा था। उन्होंने जिन समस्याओं को उठाया था उन्हें अब तक हल नहीं किया गया है। इस प्रकार के हालात ने नागरिकों के अंदर न्याय व्यवस्था के सही तरीके से काम करने और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच आपसी भरोसे को लेकर शक पैदा कर दिया है। मौजूदा सरकार संविधान, कानून की किताबों और सेक्युलरिज़्म, लोकतंत्र और कानून में बराबरी जैसे सरकारी सिद्धांतों को अपने साम्प्रदायिक एजेंडे को लागू करने में सबसे बड़ी रूकावट समझती है। न्यायपालिका को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश में बीजेपी सरकार जजों को साम्प्रदायिक और राजनैतिक बुनियादों पर बांट देना चाहती है। इस प्रकार के हालात को खत्म करने की सबसे पहली ज़िम्मेदारी चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों की है। हम सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से अपील करते हैं कि वे इस प्रकार की शैतानी चालों के मुकाबले में एक साथ मज़बूती से खड़े होकर न्यायपालिका की दियानतदारी का प्रदर्शन करें। उनहें चाहिए कि वे न्यायपालिका को दबाने के किसी भी राजनैतिक एजेंडे का शिकार न हों और उससे कभी शिकस्त न खाएं। बैठक ने देश की जनता से अपील की कि वे न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशों के खिलाफ आगे आएं क्योंकि एक तानाशाही राज में भी हमारी आखरी उम्मीदें उसी से जुड़ी होती हैं।

ए.एम.यू को निशाना बनाना बंद करो

एक दूसरे प्रस्ताव में पॉपुलर फ्रंट की एन.ई.सी की बैठक ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए.एम.यू) के छात्रों पर हिंदू युवा वाहिनी और युपी पुलिस द्वारा हमले की कड़ी निंदा की। पॉपुलर फ्रंट ने आरएसएस के नापाक मंसूबों से विश्वविद्यालय को बचाने के लिए छात्रों के

जारी संघर्ष का समर्थन किया। 1938 में लगाई गई एक तस्वीर को लेकर किसी संस्था पर हमला करना बड़ी ही अजीब बात है। यकीनन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर किया गया हमला सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं और हाशिये पर डाल दिये गए मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने वाली संस्थाओं के खिलाफ संघ परिवार की जारी कोशिशों की ही एक कड़ी है। अल्पसंख्यक संस्थाओं की सुरक्षा के बजाए, जामिया मिल्लिया के अल्पसंख्यक दर्जे पर सवाल खड़ा करके बीजेपी सरकार ने पहले ही ऐसे हालात पैदा कर दिये हैं कि ये संस्थाएं ऐसे हमलों से असुरक्षित हो गई हैं। बैठक ने केंद्र व राज्य सरकार से ए.एम.यू कैम्पस में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और छात्रों पर हमला करने वाले साम्प्रदायिक गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अपील की।

सरकारों से इबादत की आज़ादी को सुनिश्चित बनाने की अपील

एक अन्य प्रस्ताव में पॉपुलर फ्रंट की एन.ई.सी की बैठक ने हरियाणा सरकार से अपील की है कि वह आम जगह पर नमाज पढ़ने का आरोप लगाकर मुसलमानों पर हमला करने वाले गुंडों को काबू करे। उल्लेखनीय है कि 4 मई को गुरूग्राम में कुछ हिंदुत्वा के गुंडों ने कम से कम दस स्थानों पर भड़काऊ नारेबाज़ी करते हुए मुसलमानों को जुमे की नमाज़ पढ़ने से रोकने की कोशिश की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साम्प्रदायिक दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय ऐसा बयान दिया जिससे इस आपराधिक कृत्य को हौसला मिलता है। अधिकतर कस्बों में विभिन्न धार्मिक वर्गों की ओर से आम जगहों पर अवैध निर्माण किये गए हैं। एक या एक से ज्यादा धर्मिक जुलूस या त्योहार हर हफ्ते भारत की सड़कों पर निकाले और मनाए जाते हैं। अगर कार्यवाही होनी ही चाहिए तो ऐसे सभी धार्मिक कामों पर होनी चाहिए, और वह भी कानून लागू करने की जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा और कानून के मुताबिक होनी चाहिए न कि इन साम्प्रदायिक गुंडों के द्वारा। विभिन्न शहरी इलाकों में मुसलमानों को मजबूरन सड़कों के किनारे नमाज़ पढ़नी पड़ती है, क्योंकि सत्तारूढ़ सरकारों ने न केवल नई मस्जिदें बनाने की उनकी दरख्वास्तों को रद्द किया है बल्कि टूटी फूटी मस्जिदों की मरम्मत कराने से भी उन्हें रोका है। बैठक ने केंद्र व राज्य सरकार से मस्जिदों के निर्माण पर लगाई गई गैरज़रूरी पाबंदियों को हटाने और शहरों में मुसलमानों को जुमे की नमाज़ के लिए मुनासिब स्थानों की तलाश में आ रही परेशानियों का बेहतर हल तलाश करने में उनकी मदद करने की अपील की।

डॉ मुहम्मद शमून
डायरेक्टर, जनसंपर्क
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
मुख्यालय, नई दिल्ली